PAPERS LAID ON THE TABLE (*contd.*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI SURYAKANTA PATIL): Sir, on behalf of Shri Chandra Sekhar Sahu, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report of the National Institute of Rural Development (NIRD), Hyderabad, for the year 2007-2008.

(b) Annual Accounts of the National Institute of Rural Development (NIRD), Hyderabad, for the year 2007-2008, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Institute.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above. [Placed in Library. *See* No. L.T. 10828/09]

———————

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Loss of revenue of the Government caused by Swan Telecom

SHRI SABIR ALI (Bihar): Sir, there is a company known as Swan Telecom has given a licence and it is believed that there are irregularities and under-hand dealings as a result of which the Government has suffered a loss of tens of crores of rupees. That has to be debated in the House.

Implementation of the Recommendations of the Usha Mehra Committee Report on Reservation for SCs

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, केन्द्र सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की केवल कुछ सब-कास्ट्स ही रिज़र्वेशन का फायदा उठा पाई हैं, जबकि ज्यादातर बैकवर्ड कास्ट्स और पुअर सब-कास्ट्स को रिज़र्वेशन का कोई खास फायदा नहीं हुआ है। हालात ये हैं कि अब भी वे बेहद पिछड़े और गरीब हैं। इन हालातों के मद्देनज़र, हमारे इस प्रपोज़ल पर आन्ध्र प्रदेश में शैड्यूल्ड कास्ट्स को सब-कैटेगरीज़ बना कर, उनको 15% कोटा में डिवाइड करने के पिछले सिस्टम को फिर से restore किया जाए। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इसके लिए एग्री हो गई है और ऊषा मेहरा कमीशन ने भी ऐसी व्यवस्था करने की सिफारिश कर दी है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने ऊषा मेहरा कमीशन की रिपोर्ट को ऑलरेडी पांच मिनिस्ट्रीज़ में सर्कुलेट कर दिया है। इस बात को भी करीब एक साल हो गया है और इस रिकमेंडेशन के इम्प्लिमेंटेशन में देरी की वजह से आन्ध्र प्रदेश में मादिगा, जो कि शैड्यूल्ड कास्ट्स में एक जाति है, एवं दूसरी अन्य बहुत सी बैकवर्ड अनुसूचित जातियों में रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा है। इसी के लिए जैसा कि constitutionally जरूरी है, केन्द्र सरकार पंजाब और हरियाणा में लागू SCs की sub-categories की तरह आन्ध्र प्रदेश में भी और शैड्यूल्ड कास्ट के ABCD groups में sub-categorisation के लिए तथा ऐसे ग्रुप्स बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को ऑथोराइज करने लिए इस आखिरी सैशन में जरूरी है कि constitution amendment Bill लाए। आन्ध्र प्रदेश सरकार को पिछले एक दशक से चले आ रहे इस प्रोपोजल को जल्दी-से-जल्दी इम्प्लीमेंट करना ही होगा वरना आंध्र प्रदेश में अब तक रिजर्वेशन का लाभ न उठा सकी SC sub-castes की भारी आबादी के resentment और गुस्से पर काबू बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके थ्रू प्रधान मंत्री और कैबिनेट से अनुरोध करूँगा कि शीघ्र ही ऊषा मेहरा समिति की इस सिफारिश पर